

जीवाश्म से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के जोखिम

प्रलम्बित के लिये:

स्वच्छ ऊर्जा, हरित संक्रमण, शुद्ध शून्य, जीवाश्म ईंधन।

मेन्स के लिये:

जीवाश्म से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण की चुनौतियाँ।

चर्चा में क्यों?

ग्लोबल एनवायरनमेंटल चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत का वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था की बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता तथा स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

अध्ययन के नष्कर्ष:

- **संक्रमण के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:**
 - भारत का वित्तीय क्षेत्र जीवाश्म ईंधन से संबंधित गतिविधियों के लिये अत्यधिक जोखिम में है और जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण का इस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
 - तेल और गैस नष्करण खनन ऋण का 60% हिस्सा है।
 - **व्यवसाय क्षेत्र का 20% ऋण पेट्रोलियम रफाइनिंग और संबंधित उद्योगों के लिये है।**
 - बजिली उत्पादन कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कुल बकाया ऋण का 5.2% है।
- **व्यवसायों की कमी:**
 - भारत के वित्तीय संस्थानों में ऐसे व्यवसायों की कमी है जिनके पास जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण हेतु संस्थानों को उचित सलाह देने की विशेषज्ञता होती है।
 - सर्वेक्षण किये गए दस प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से केवल चार पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ESG) जोखिमों पर जानकारी एकत्र करते हैं और ये फर्म भी व्यवस्थित रूप से उस डेटा को वित्तीय नयोजन में शामिल नहीं करते हैं।
- **घाटे और तनाव को सहने की कम क्षमता:**
 - उच्च कार्बन उद्योग- वद्युत उत्पादन, रसायन, लौह एवं इस्पात तथा वमिनन में भारतीय वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण का 10% हिस्सा है।
 - हालाँकि उद्योग भी भारी ऋणग्रस्त हैं और इसलिये घाटे एवं तनाव को सहन करने की इनकी कम वित्तीय क्षमता है।
 - यह संक्रमण से जुड़े भारत के वित्तीय क्षेत्र के जोखिम को उजागर करेगा।
- **अधिक प्रदूषणकारी एवं अधिक महँगी ऊर्जा आपूर्ति:**
 - भारतीय बैंकों और संस्थागत नविशकों के वित्तीय नरिणय देश को अधिक प्रदूषणकारी और अधिक महँगी ऊर्जा आपूर्तिकी ओर ले जा रहे हैं।
 - उदाहरण के लिये वद्युत क्षेत्र को दिये गए कुल बैंक ऋण का केवल 17.5% वशुद्ध रूप से नवीकरणीय ऊर्जा हेतु प्रदान किया गया है।
 - नतीजतन भारत में वशुद्ध औसत की तुलना में कार्बन-स्रोतों से अधिक वद्युत उत्पादन होता है।
 - वर्तमान में कोयले का भारत के प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में लगभग 44% का योगदान है तथा वद्युत वितरण में इसका 70% हिस्सा है।
 - देश के कोयले से चलने वाले वद्युत संयंत्रों की औसत आयु 13 वर्ष है और भारत में 91,000 मेगावाट की नई प्रस्तावित कोयला क्षमता पर काम चल रहा है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
 - **राष्ट्रीय वद्युत योजना 2022** के मसौदे के अनुसार, वद्युत उत्पादन में कोयले की हसिसेदारी वर्ष 2030 तक घटकर 50% हो जाएगी।
- **क्षमता:**
 - वर्तमान ऋण और नविश पैटर्न से पता चलता है कि भारत का वित्तीय क्षेत्र संभावित संक्रमण जोखिमों से भलीभाँति अवगत है।
 - हालाँकि जोखिम का दूसरा पक्ष स्थायी परसिंपत्तियों और गतिविधियों की ओर वित्त को स्थानांतरित करने का सुलभ अवसर है।

- वर्ष 2021 में भारत ने वर्ष 2070 तक **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन** के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रतबिद्धता व्यक्त की है।
- भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी आधी बजिली ज़रूरतों (50%) को पूरा करने की योजना की भी घोषणा की है।
- इन प्रतबिद्धताओं को पूरा करने के लिये कम-से-कम एक ट्रिलियन डॉलर के वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित वर्तमान स्थिति और प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों का वविरण दीजिये। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (Light Emitting Diodes- LED) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्त्व पर संक्षेप में चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2016)

प्रश्न. क्या कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गरीब के बावजूद जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र को बनाए रखा जाना चाहिये? आर्थिक विकास के लिये भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2014)

[स्रोत: द हिंदू](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/risk-of-moving-from-fossils-to-clean-energy>

